



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11072025-264543
CG-DL-E-11072025-264543

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3027]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 11, 2025/आषाढ़ 20, 1947

No. 3027]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 11, 2025/ASHADHA 20, 1947

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 2025

का.आ. 3097(अ).— केन्द्रीय सरकार, धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 43 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायामूर्ति के परामर्श से भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 372(अ) तारीख 5 फरवरी, 2016 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना की तालिका में आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित क्रम सं. 1 के सामने स्तंभ 3 और 4 में विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां क्रमशः अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

(3)	(4)
“केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो मामलों के लिए प्रधान विशेष न्यायाधीश न्यायालय, विशाखापट्टनम	पार्वतीपुरम् मान्यम, श्रीकाकुलम, विजयनगरम्, विशाखापट्टनम, अल्लुरिसीताराम राजू, अनकपल्ली, काकीनाडा, पूर्वी गोदावरी, कोनासीमा, पश्चिमी गोदावरी, एल्लुरु, नंदमूरी तारक रामाराव, कृष्णा राजस्व जिले।
	केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा संचालित अन्वेषणों/फाइल चार्ज सीटों से उत्पन्न होने वाले धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) के मामलों के संबंध में संपूर्ण आंध्र प्रदेश राज्य।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो मामलों के लिए अपर विशेष न्यायाधीश न्यायालय, विशाखापट्टनम	पालनाडू, बापतला, गुटूर, प्रकाशम, नांदयाल, कुरनूल, आनंतपुर, वाईएसआर कडप्पा, नेल्लोर श्री सत्य साई, अन्नामया, चित्तूर और तिरुपति राजस्व जिले।”।

[फा. सं. सी-18015/1/2025-एडी.ईडी]

राजीव लोचन, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ. 372(अ) तारीख 5 फरवरी, 2016 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन का.आ. 966(अ) तारीख 27 मार्च, 2017 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th July, 2025

S.O. 3097(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 43 of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003) and in consultation with the Chief Justice of High Court of Andhra Pradesh, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii) *vide* number S.O. 372(E), dated the 5th February, 2016 namely:-

In the said notification, in the Table, against serial number 1 relating to the State of Andhra Pradesh, after existing entries in columns (3) and (4), the following entries shall respectively be inserted, namely:-

(3)	(4)
"Principal Special Judge Court for Central Bureau of Investigation Cases, Visakhapatnam.	Revenue districts of Parvatipuram Manyam, Srikakulam, Vizianagaram, Visakhapatnam, Alluri Sita Rama Raju, Anakapali, Kakinada, East Godavari, Konaseema, West Godavari, Eluru, Nandamuri Taraka Rama Rao, Krishna.

	Entire State of Andhra Pradesh in respect of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003) cases arising out of investigations conducted/charge sheets filed by Central Bureau of Investigation.
I Additional Special Judge Court for Central Bureau of Investigation cases, Visakhapatnam.	Revenue districts of Palnadu, Bapatla, Guntur, Prakasam, Nandyal, Kurnool, Anantpur, YSR Kadapa, Nellore Sri Satya Sai, Annamayya, Chittoor and Tirupati".

[F. No. C-18015/1/2025-Ad.ED]

RAJEEV LOCHAN, Under Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii), vide number S.O. 372(E), dated the 5th February, 2016 and was last amended *vide* S.O. 966(E) dated 27th March, 2017.